भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3077
उत्तर देने की तारीख-20/08/2025

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

3077 **श्री कपिल सिब्बल:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के कार्यान्वयन में प्रगति हुई है और वर्ष 2025-2026 में इसके लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाएगा;
(ख) जुलाई, 2025 तक मंत्रालय ने एनईपी 2020 के संबंध में कौन-कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं;
(ग) मंत्रालय वर्ष 2025 में कार्यान्वयन के लिए कौन-कौन सी एनईपी पहलों को प्राथमिकता दे रहा है; और
(घ) मंत्रालय वर्ष 2026 तक एनईपी के कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का समाधान कैसे करेगा?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) की घोषणा के बाद, इसके कार्यान्वयन के लिए स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों में कई परिवर्तनकारी बदलाव हुए हैं।

स्कूल शिक्षा में अनेक पहल जैसे कि स्कूलों के उन्नयन के लिए पीएम श्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया); सभी बच्चों के लिए समावेशी और उचित कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए समग्र शिक्षा; ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए समझ और संख्याज्ञान के साथ पढ़ने में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत); विद्या-प्रवेश-तीन महीने के खेल-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए दिशानिर्देश; शिक्षा के लिए सुसंगत बहु-मोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करने के लिए पीएम ई-विद्या, ई-बुक्स और ई-कंटेंट वाले वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में दीक्षा (ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर), परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण); निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) 1.0, 2.0 और 3.0; विद्या समीक्षा

केंद्र; एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम; शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी); शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय और उत्प्रेरित करने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा निर्माण (एनडीईएआर), 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी निरक्षरों को लक्षित करते हुए "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या उल्लास" योजना का कार्यान्वयन, आदि की गई हैं।

उच्चतर शिक्षा में, विभिन्न पहल/सुधार जैसे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीआरएफ) और स्नातक कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अर्हता रूपरेखा (एनएचईक्यूएफ) के साथ दिशानिर्देश/विनियमन जैसे पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या रूपरेखा; उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक कार्यक्रम में एकाधिक प्रवेश और निकास; उच्चतर शिक्षा संस्थाओं का बहु-विषयक संस्थाओं में रूपान्तरण; एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों का अध्ययन करना; स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर आईडी) जो पूर्व-प्राथमिक से उच्चतर शिक्षा तक उनकी शैक्षिक यात्रा और उपलब्धियों को चिह्नित करने के लिए आजीवन पहचान के रूप में कार्य करेगी; मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत के साथ एक सरल, पारदर्शी और विद्यार्थी-अनुकूल और पूर्णत: डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम के समानांतर मुक्त, गारंटर मुक्त ऋण को सक्षम बनाना; ओडीएल/ऑनलाइन शिक्षा के परिशोधित विनियमन; स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से नियमित पाठ्यक्रमों में 40% क्रेडिट तक की अनुमति देना; विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत मौजूदा जनशक्ति के कौशल और कौशल उन्नयन और पुनःकौशलीकरण को उन्नत करने के उद्देश्य से नए स्वयं प्लस पोर्टल का शुभारंभ; उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के प्रशासन में समर्थ के माध्यम से प्रवेश से लेकर डिग्री प्रदान करने तक प्रौद्योगिकी का एकीकरण; उद्योग विशेषज्ञों के साथ कार्य करने के लिए एचईआई को सक्षम बनाने के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस संबंधी दिशानिर्देश; भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश देने हेतु अतिरिक्त सीटों के लिए दिशानिर्देश; अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की बढ़ती प्रतिष्ठा; शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल करना आदि किए गए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय उच्चतर शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के अंतरराष्ट्रीयकरण के निरंतर प्रयासों ने प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों को भारतीय शिक्षा परिदृश्य में प्रवेश करने में सक्षम बनाया है। भारत में अपतटीय परिसर स्थापित करने के लिए यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इटली जैसे देशों के विश्व स्तर के 11 विश्वविद्यालयों को आशय पत्र जारी किए गए हैं। यह उल्लेखनीय है कि साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में गुरुग्राम में अपने परिसर का संचालन आरंभ कर दिया है। दो ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों- डीकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय- ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में प्रचालन आरंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, यूके स्थित क्वीन्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कोवेंट्री विश्वविद्यालय को भी गिफ्ट सिटी में परिसर स्थापित करने का अनुमोदन मिल गया है। आईआईटी मद्रास (जंज़ीबार) और आईआईटी दिल्ली (अबू धाबी) जैसे भारतीय संस्थान वैश्विक स्तर पर विस्तार कर रहे हैं। आईआईएम, अहमदाबाद और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सरकार ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक नगर

(डीआईएसी) में आईआईएम अहमदाबाद दुबई परिसर की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

वैश्विक रैंकिंग में भारत की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, क्यूएस रैंकिंग 2026 में 54 भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को स्थान मिला है। क्यूएस 2026 में, 54 भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को स्थान दिया गया है, जबकि क्यूएस 2021 में यह संख्या 28 थी। क्यूएस 2026 में, शीर्ष 500 में 10 भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एशिया 2025 में भारत का दूसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है, जिसमें 163 विश्वविद्यालय और 7 संस्थाएं शीर्ष 100 में शामिल हैं। वर्ष 2025 की क्यूएस विषय रैंकिंग में 79 भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थाएं शामिल थीं, जो गत वर्ष के 69 से 10 अधिक है और यह 14% की वृद्धि दर्शाता है। भारतीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व 533 प्रविष्टियों में किया गया, जो पिछले संस्करण में 424 प्रविष्टियों से 25.7% अधिक है।

भारत सरकार (जीओआई) के पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेत महानियंत्रक कार्यालय की वार्षिक रिपोर्ट (2023-24) के अनुसार, भारत ने बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसमें 2023-24 में 92,168 पेटेंट के आवेदन किए गए हैं - यह वर्ष 2014-15 से 115% से अधिक की वृद्धि है। इस वृद्धि का एक प्रमुख कारक शैक्षणिक संस्थाओं का योगदान रहा है। घरेलू शिक्षण संस्थानों द्वारा पेटेंट आवेदन वर्ष 2021-22 में 7405 से वर्ष 2023-24 में 23,306 तक तीन गुना से अधिक हो गए हैं। भारत में नवाचार को बढ़ावा देने में शैक्षणिक संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वर्ष 2023-24 में, उन्होंने 23,306 पेटेंट आवेदन किए, जो उस वर्ष आवेदित सभी पेटेंट का 25.28% है। यह अनुसंधान और नये विचारों के प्रति उनके सुदृढ़ और बढ़ते योगदान को दर्शाता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 'अनुसंधान एवं विकास संबंधी आंकड़ों पर एक नज़र 2022-23' के अनुसार, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग (एस एंड ई) में पीएचडी की संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के कारण वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) में भारत की रैंकिंग को वर्ष 2015 के 81वें स्थान से वर्ष 2020 में 48वें स्थान पर पहुंच गई है और वर्तमान में वर्ष 2024 में यह 39वें स्थान पर है।

"भारत में एआई बनाएं और भारत के लिए एआई को काम में लाएं" की संकल्पना को साकार करने के लिए, सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 की अवधि में 990.00 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में तीन उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया था। शिक्षा मंत्रालय ने तीन उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना के लिए तीन शैक्षणिक संस्थानों आईआईएससी बेंगलुरु में स्वास्थ्य में एआई का सीओई, आईआईटी रोपड़ में कृषि में एआई का सीओई और आईआईटी कानपुर में संधारणीय शहरों में एआई का सीओई। को अनुमोदित किया था। इसके अतिरिक्त, बजट वर्ष 2025-26 में 500.0 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के लिए शिक्षा में एक नए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की घोषणा की गई है।

बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार, भारतीय भाषा पुस्तक योजना की परिकल्पना अगले तीन वर्षों में डिजिटल प्रारूप में 22 भारतीय भाषाओं में विभिन्न स्कूल और उच्चतर शिक्षा विषयों में पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने के लिए की गई है।

एनईपी 2020 में इसके कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग समय-सीमा, सिद्धांत और कार्यप्रणाली का प्रावधान किया गया है। बड़ी संख्या में पहलों को लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनईपी 2020 का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य समान रूप से जिम्मेदार हैं। तदनुसार, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारें, शिक्षा से संबंधित मंत्रालयों, स्कूल और उच्चतर शिक्षा के विनियामक और कार्यान्वयन निकायों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल आदि ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए पहलें की हैं।

एनईपी के कार्यान्वयन के लिए जागरूकता पैदा करने और नवीन विचारों पर चर्चा करने के लिए, समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थानों, अन्य हितधारकों के साथ कार्यशालाओं/परामर्श-सह-समीक्षा बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है। जून 2022 में गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन; जून 2022 में आयोजित मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन; अगस्त 2022 में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक; अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022, 2023 और 2024, 27 जुलाई 2024 को आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में एनईपी 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को लागू करने हेतु विभिन्न दृष्टिकोणों और पद्धतियों का प्रसार करने के लिए दिनांक 12 और 13 नवंबर 2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवों के साथ उच्चतर और तकनीकी शिक्षा पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का दो दिवसीय सम्मेलन दिनांक 10 और 11 जुलाई 2025 को केवडिया, गुजरात में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य शैक्षिक परिवर्तन के वाहक के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की भूमिका और 2047 तक विकसित भारत में उनके योगदान पर ध्यान केंद्रित करना, प्रगति की समीक्षा करना और भविष्य की रूपरेखा निर्धारित करना था।

हाल ही में, एनईपी 2020 की घोषणा के 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दिनांक 29 जुलाई, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए नवोन्मेषी दृष्टिकोण पर चर्चा और विचार-विमर्श करना था। समागम में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों और अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया।

****